

दक्षिण एशिया में मुद्रास्फीति की गतिशीलता*

माइकल देब्रत पात्र

नमस्कार ! महामारी के बाद सार्कफाइनेंस के तत्वावधान में इस पहली प्रत्यक्ष संगोष्ठी में भाग लेने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सहभागी केंद्रीय बैंकों का गर्मजोशी से स्वागत है।

सुश्री डेचन पेलजोम, कार्यकारी निदेशक, भूटान रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी, को बधाई।

हमें, अपने साथ वित्त मंत्रालय के सहयोगियों, और हमारे केंद्रीय बैंकों, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अप्रत्यक्ष प्रतिभागियों को साथ पाकर खुशी हो रही है। मैं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सहयोगियों, जो विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के साथ इसमें शामिल हुआ हूँ।

यह संगोष्ठी, मार्च 2021 में सार्कफाइनेंस गवर्नर समूह की 41वीं बैठक में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता की पूर्ति का प्रतीक है। हमारे देशों में घटनाक्रमों और वैश्विक मुद्रास्फीति संकट को देखते हुए, संगोष्ठी का विषय - मुद्रास्फीति की गतिशीलता और दक्षिण एशिया में इस पर नियंत्रण - से अधिक सामयिक और प्रासंगिक नहीं हो सकता था। व्यापक दृष्टिकोण में, सार्कफाइनेंस के अधिदेश के तहत इस प्रकार के सेमिनार और कार्यशालाएं, ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ व्यक्तिगत बातचीत और हमारे जुड़ाव को बेहतर करने का एक प्रभावी अवसर साबित हुए हैं। हमारा अगला सेमिनार सार्कफाइनेंस डेटाबेस पर होगा, जिसकी मेज़बानी मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा की जाएगी।

* 24 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित सार्कफाइनेंस सेमिनार में डॉ. माइकल देब्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। स्मिता शर्मा, सोमाश्री तिवारी और अजेश पालयी के बहुमूल्य इनपुट और विनीत कुमार श्रीवास्तव की संपादकीय सहायता के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।

सार्क: हमारा इतिहास

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का गठन 1985 में - हमारे क्षेत्र में साझा समझ और सहयोग को बढ़ावा देने की सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में - किया गया था। वर्तमान में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, सार्क के सदस्य हैं।

वर्षों से, हमारे देशों ने हमारे मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और साझा इतिहास के अलावा, व्यापार, धन-प्रेषण और वित्तीय लेनदेन के रूप में मजबूत संबंध विकसित किए हैं। अब हम इस क्षेत्र की पूरी संवृद्धि क्षमता का उपयोग करके आर्थिक विकास और समृद्धि को गति देने के लक्ष्य के साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने की आशा रखते हैं।

सार्कफाइनेंस: एक अवलोकन

सार्कफाइनेंस की स्थापना 1998 में हमारे केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त सचिवों के संपर्क-तंत्र के रूप में समष्टि आर्थिक नीतियों पर संवाद और आपसी अनुभवों और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए की गई थी। सार्कफाइनेंस को जनवरी 2002 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित 11वें सार्क शिखर सम्मेलन में औपचारिक मान्यता मिली।

पिछले दो दशकों में, हमारे केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग में विस्तार और मजबूती आए हैं। स्वैप सुविधा, जो इस सहयोग की आधारशिला रही है, ने महामारी के दौरान बाह्य-क्षेत्र के दबावों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने सार्क-सहयोगियों को कई क्रेडिट लाइनों के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

नीतिगत इंटरफेस, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान ने इस जुड़ाव को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से, अनुसंधान और नीति संचालित सहयोगी अध्ययन, और इस तरह के संगोष्ठियों और सेमिनारों ने

प्रत्येक देश और क्षेत्र द्वारा अनुभव किए गए मुद्दों, चुनौतियों और सफलताओं को सामने लाकर इस पूरे प्रयास को सुगम बनाया है।

सार्कफाइनेंस के तहत कुछ पूर्ण कार्यों का परिचय देने के लिए, गवर्नर समूह बैठक ने समष्टि आर्थिक स्थितियों और नीतियों पर हमारे सहयोग और संवाद को औपचारिक रूप दिया है। सार्कफाइनेंस वेबसाइट को 2011 में विकसित और आरंभ किया गया। सार्कफाइनेंस डेटाबेस 26 मई 2016 को मुंबई में आयोजित गवर्नर सम्मेलन में लाइव हुआ था। अर्धवार्षिक सार्कफाइनेंस ई-न्यूजलेटर का पहला अंक दिसंबर 2006 में प्रकाशित हुआ था। 2020-21 में भारत की अध्यक्षता के दौरान, हमारे केंद्रीय बैंकों के बीच कनेक्टिविटी के नेटवर्क के रूप में 'सार्कफाइनेंस सिंक' नामक पोर्टल बनाया गया था। छात्रवृत्ति योजना का दायरा और कवरेज अधिक विश्वविद्यालयों, अधिक केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित पाठ्यक्रमों को शामिल करके और एक वर्ष में दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि और छात्रवृत्ति की संख्या दोनों में वृद्धि करके विस्तारित किया गया था। एक नए डिजाइन और प्रारूप के साथ और सामयिक आलेखों तक विस्तार कर, सार्कफाइनेंस न्यूजलेटर को नया रूप देने का भी प्रयास किया गया है। हमारे आभासी सेमिनारों ने महामारी के दौरान हमारे जुड़ाव को चालू रखा। वित्तीय समावेश प्लेटफॉर्म - वित्तीय समावेश और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सार्क केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई पहलों - का एक केंद्र है जिसने इसे अखिल-क्षेत्रीय दृष्टिकोण से नीति निर्माण को समृद्ध कर इसे बेहतर बनाया है। क्षमता निर्माण पर सहयोग - विशेष रूप से विभिन्न विषयों पर समवेत अध्ययन - बढ़ाने की पहल भी उल्लेखनीय है।

समष्टि आर्थिक घटनाएँ: अवसर और चुनौतियाँ

हमारे देशों ने सभी सदस्यों के अंशदान के साथ एक विशेष सार्क कोविड-19 आपातकालीन कोष की स्थापना करके कोविड-19 से सामूहिक लड़ाई के लिए साथ जुटे हैं। टीकों के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में, भारत समान पहुंच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने जनवरी 2021 में अपनी वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत से एक महीने के भीतर कई सार्क देशों को टीके उपलब्ध कराए हैं।

आरबीआई डिजिटल बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पेमेंट विजन 2025 में, हमारे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रुपये कार्ड्स की वैश्विक पहुंच शामिल है। उदाहरण के लिए, भूटान और भारत ने रुपये कार्ड को लेकर सहयोग बनाया है ताकि भूटानी बैंक अपने नागरिकों को रुपये कार्ड जारी कर सकें।

सार्क देशों के कुल निर्यात में अंतःसार्क व्यापार का हिस्सा 2010 में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 7.1 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह, सार्क देशों के कुल आयात में अंतःसार्क व्यापार का हिस्सा 2010 में 3.6 प्रतिशत से 2020 में 5.0 प्रतिशत बढ़ गया है। व्यापार के विस्तार की गति धीमी बनी हुई है, हालांकि, आसियान जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों के सापेक्ष भी।

महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित होने के कारण, इस क्षेत्र में 2020 में आर्थिक संकुचन देखा गया। 2021 के दौरान पूरे क्षेत्र में बहुस्तरीय गति और नुकसान के साथ एक कमजोर सुधार हुआ। हमारे क्षेत्र के कई हिस्सों में महामारी के निशान अभी भी गहरे और दर्दनाक हैं।

2022 में, लगातार उच्च मुद्रास्फीति ने जोर पकड़ लिया है, जो 2021 में हुई प्रारंभिक प्रगति के कमजोर होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। कई सदस्य-देश उच्च स्तर में द्विअंकीय मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, जिसमें की उंची कीमतों और आपूर्ति शृंखला दबावों के रूप में वैश्विक प्रसार-प्रभाव ने आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है। इस साल फरवरी से आवश्यक वस्तुओं की कमी और भोजन और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने हमारे लोगों की आजीविका और कल्याण को खतरे में डाल दिया है।

बाहरी मोर्चे पर, व्यापार आघातों और सख्त वैश्विक वित्तीय स्थितियों के कारण व्यापक चालू खाता घाटा, पूंजी बहिर्वाह, घरेलू वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता उत्पन्न हुए एवं बाहरी कमजोरियाँ बढ़ीं और आरक्षित निधि को नुकसान पहुँचा। हममें से कुछ कर्ज संकट का भी सामना कर रहे हैं। विभिन्न बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग डाउनग्रेड करने से बाधित अंतरराष्ट्रीय

वित्तीय बाजारों तक पहुंच ने बाहरी तरलता और वित्तपोषण की स्थिति को खराब कर दिया है। हममें से कुछ को इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बहुपक्षीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता है।

संगोष्ठी का विषय

इस परिवेश में संगोष्ठी का विषय महत्वपूर्ण है। महामारी के झटके और हाल ही में युद्ध से उत्पन्न मुद्रास्फीति का राष्ट्रीय विस्तार, एक संकट बना हुआ है। जुलाई 2022 के आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार, जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी और कीमतों के दबाव-विस्तार के कारण 2022 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 6.6 प्रतिशत और उदीयमान बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 9.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिससे समष्टि आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है।

इसकी प्रतिक्रिया में, दशकों में अब तक देखी गई सबसे समकालिक और अग्रसक्रिय मौद्रिक नीति को सख्त किया जा रहा है। नतीजतन, जैसे-जैसे तरलता और मौद्रिक स्थितियां सख्त हुई हैं, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी या हार्ड लैंडिंग की संभावना उन स्तरों तक बढ़ गई है जो अतीत में वास्तविक मंदी से पहले देखे गए थे। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक आक्रामक रूप से अपनी विश्वसनीयता हासिल करने और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को नियंत्रित किया जा सके और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाया जा सके।

देश के आकार, आर्थिक और सामाजिक विकास, भूगोल, जनसंख्या, व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र की विविधता के बावजूद, मुद्रास्फीति का यह भयावह भूत हम सभी को परेशान करता है। भोजन हमारी औसत खपत बास्केट के साथ-साथ हमारे मूल्य सूचकांकों का एक बड़ा हिस्सा है और पूरे क्षेत्र में उपभोक्ता कीमतों में इसकी हिस्सेदारी 35 से 47 प्रतिशत के बीच है। गरीबी से जूझ रही हमारी आबादी के बड़े हिस्से को देखते हुए, दक्षिण एशिया खाद्य मुद्रास्फीति के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। इसके अलावा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खाद्य कीमतें बढ़ रही हैं जो दूसरे दौर के प्रभावों को ट्रिगर

कर सकती हैं, जिससे मुद्रास्फीति के स्थायी और निरंतर बना रह सकता है। इसके अलावा, तेल आयात पर निर्भरता ने हमारे देशों को आमतौर पर व्यापार और आपूर्ति के झटकों के प्रति संवेदनशील बना दिया है। नतीजतन, सामान्य कारकों के कारण इस क्षेत्र में मुद्रास्फीति में तेज बदलाव देखने को मिला। दूसरी ओर, हमारे नीतिगत ढाँचे में विविधता है जो देश-विशिष्ट परिस्थितियों को दर्शाते हैं और यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के हमारे दृष्टिकोण को आकार देता है। हमारी विनिमय दर व्यवस्थाएं भी इस विविधता को दर्शाती हैं।

मुद्रास्फीति के संकट से निपटना जटिल हो गया है क्योंकि हम निरंतर वैश्विक प्रभाव-प्रसार से जूझ रहे हैं। यह क्षेत्र अब एक जबरदस्त विकासपरक चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई सबसे विकट दिखती है। हमारे देशों ने राजकोषीय घाटे में तेज वृद्धि और भुगतान संतुलन का बिगड़ना भी अनुभव किया है। आर्थिक गतिविधियों, रोजगार और निर्यात आय में अभूतपूर्व मंदी की पृष्ठभूमि में भविष्य अनिश्चित और निराशाजनक दिखाई देता है। हमारी संवृद्धि संभावनाओं के सामने जोखिम हैं। आर्थिक-मंदी की काली छाया हम पर और हमारे नजरिये पर मंडरा रही है।

भारतीय अनुभव

भारत में, हमने 2016 से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को अपनाया है, जिसमें हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के लक्ष्य को इसके आसपास +/- 2 प्रतिशत के टॉलरेंस बैंड के भीतर परिभाषित किया गया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा नीतिगत निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। लक्ष्य से मुद्रास्फीति परिणामों के विचलन के मामले में विधि और संबंधित नियमों द्वारा ढांचे में निहित सख्त जवाबदेही मानदंड हैं। जहाँ, 2016-20 के दौरान मुद्रास्फीति औसतन 4 प्रतिशत से कम थी, यह 2020-21 में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई – जो महामारी की पहली लहर का वर्ष था। यद्यपि यह अगले वर्ष, यानी 2021-22 से 5.5 प्रतिशत तक कम हो गया और 2022-23 में 4.5 प्रतिशत तक और कम होने का अनुमान लगाया गया था, जैसा कि हाल ही में फरवरी

2022 तक, यूक्रेन युद्ध ने नजरिये को काफी बदल दिया है। हालांकि यह इस साल अप्रैल में अपने चरम 7.8 प्रतिशत से कम होता हुआ प्रतीत होता है, इससे पहले कि हम आश्चर्य हों कि यह एक स्थायी प्रवृत्ति है, हम आने वाले डेटा की प्रतीक्षा करना पसंद करेंगे। जहाँ, वैश्विक और घरेलू स्तर पर अंतरराष्ट्रीय जिंसों की कीमतों और आपूर्ति शृंखला दबावों में कुछ नरमी, सकारात्मक संकेत है, वहीं संभावित दूसरे क्रम के प्रभाव और मुद्रास्फीति के मुख्य घटक पर कच्चे माल की लागत के दबाव के रूप में ऊर्ध्वोन्मुखी जोखिम बने हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-मार्च) के लिए समग्र रूप से, आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 6.7 प्रतिशत रहेगी।

तदनुसार, आरबीआई ने अप्रैल में नीतिगत दर के दायरे को कम करने के अलावा अब तक नीतिगत दर में संचयी 140 आधार अंकों की वृद्धि के साथ एक अग्रसक्रिय मौद्रिक नीति कर्वाइ शुरू की है, जिसने मुद्रा बाजार दरों को महामारी के निम्न स्तर से 40 आधार अंक उपर खींच लिया है। अगस्त की शुरुआत में अपनी नवीनतम बैठक में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजनकारी नीति की बहाली पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया कि संवृद्धि में सहायक बन कर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे। इसके साथ ही, आरबीआई, सुविचारित बहु-वर्षीय समय सीमा में महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में डाली गई चलनिधि की निकासी में लगा हुआ है।

चूँकि मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, मौद्रिक नीति ढांचे में एक मध्यवर्ती लक्ष्य की भूमिका निभाता है, आरबीआई ने मुद्रास्फीति की निगरानी को मजबूत करने और पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करने के लिए कई पहल किए हैं। भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों के दायरे और गहराई को बढ़ाने के अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) सहित वैकल्पिक पूर्वानुमान तकनीकों और मॉडलों का पता लगाने के लिए एक डेटा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भोजन के बड़े हिस्से को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आपूर्ति-जनित आघात लग सकते हैं, मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान की सहायता के लिए डेटा साइंस लैब में रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल की स्थिति का आकलन

करने का काम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा, विश्वास विश्लेषण के माध्यम से जनता की प्रत्याशाओं के आकलन के लिए नई पहल की जा रही है जिससे पूर्वानुमान प्रक्रिया और सटीकता में सुधार हो सके। हमने व्यापार निकायों, व्यापारियों, डोमेन विशेषज्ञों और क्षेत्रीय इकाइयों से बाजार आधारित आसूचना एकत्र करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। हमारा इरादा जितना संभव हो उतती उपयोगी जानकारी आत्मसात करना और मुद्रास्फीति की गतिशीलता की हमारी समझ को समृद्ध बनाना है। हालांकि, अल्पावधि में, मुद्रास्फीति का वृद्धि-पथ भू-राजनीतिक घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय जिंस-बाजार की गतिशीलता और वैश्विक वित्त बाजार के घटनाक्रमों पर निर्भर है।

समापन टिप्पणी

केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक संस्थानों के रूप में, हमें समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने एवं बनाए रखने और अपनी विकासपरक आकांक्षाओं की पूर्णता के लिए हमारी अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। हम अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज और गहन सार्वजनिक-संवीक्षा में संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करते हैं। हाल के वर्षों में हमारी भूमिका में बदलाव आया है। अंतिम ऋणदाता से हम पहला बचावकर्ता बन गए हैं। इसलिए, मुद्रास्फीति आघातों के प्रति हमारी कार्रवाई, जैसा कि हम आज सामना कर रहे हैं, प्रत्याशाओं के प्रबंधन और विश्वसनीयता को मजबूत करने पर आधारित होना चाहिए। यदि विश्वसनीयता अधिक है और झटका अस्थायी है, तो मुद्रास्फीति बिना किसी मौद्रिक नीति कार्रवाई की आवश्यकता के संतुलन में लौट आती है। दूसरी ओर, बार-बार आपूर्ति के झटके - जिनका हम अभी सामना कर रहे हैं - लागत में वृद्धि, प्रत्याशाओं, विनिमय दर और मांग चैनलों के माध्यम से दूसरे दौर के प्रभाव को ट्रिगर करते हैं और इससे अग्रसक्रिय मौद्रिक नीति कार्रवाई की जरूरत पैदा होती है। पूर्ण विश्वसनीयता के साथ भी, मौद्रिक नीति बार-बार होने वाले आपूर्ति झटकों के दूसरे दौर के प्रभावों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। यदि लंबे समय तक मुद्रास्फीति लक्ष्य पार करता है, तो यह प्रत्याशाओं को अस्थिर कर सकता है और अंततः उच्च मुद्रास्फीति में परिलक्षित हो सकता है। उच्च विश्वसनीयता, बार-बार होने वाले आपूर्ति

झटकों के दूसरे दौर के प्रभावों के लिए मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया को कम कर सकती है परंतु इसका स्थानापन्न नहीं हो सकती। वर्तमान समय में, हमारा अनुभव यह है कि मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को सामने लाकर और मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाकर विश्वसनीयता प्रदर्शित की जा सकती है। मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता का एक अन्य आयाम इसकी प्रतिक्रिया का समय है। मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया में देरी से विश्वसनीयता में और कमी आती है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाएँ बढ़ती हैं और अंततः उच्च मुद्रास्फीति से संवृद्धि प्रभावित होती है।

प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी और बाजार पहुंच के साथ सार्क में आर्थिक विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया में, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण

के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास की काफी संभावनाएं हैं। हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और अवसर का लाभ उठाना चाहिए, भले ही हम महामारी और भू-राजनीतिक घटनाओं के दुर्बल प्रभावों से उबर जाएं। इस तरह के संगोष्ठियों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और जुड़ाव से हमें क्षमता और तकनीकी कौशल निर्माण में प्रगति में मदद मिलेगी। वर्ष 2016 में तैयार किए गए क्षेत्रीय सहयोग के रोडमैप को सार्कफाइनेंस के अधिदेश के तहत, लक्ष्य और समयसीमा के साथ वर्तमान वास्तविकताओं और फोकस क्षेत्रों को शामिल करने हेतु संशोधित करने की आवश्यकता है।

मैं इस संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद !